RNI No.—UPHIN/2017/74904 ISSN : 2581–687X

शिक्षा जगत में नवोन्मेष केंद्रित हिंदी में प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका

शैक्षिक उन्मेष

खंड–4, अंक–1; आश्विन–मार्गशीर्ष, 2077/अक्टूबर–दिसंबर, 2020

© सचिव, केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल, आगरा

प्रकाशक – अध्यापक शिक्षा विभाग
केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा

संपादकीय कार्यालय – अध्यापक शिक्षा विभाग
केंद्रीय हिंदी संस्थान
हिंदी संस्थान मार्ग, आगरा – 282005
फोन/फैक्स – 0562–2530684
ई–मेल : departmentofteacheredu0@gmail.com

सदस्यता शुल्क – व्यक्तिगत –प्रति अंक ₹ 40/–, वार्षिक – ₹ 150/–
संस्थागत – वार्षिक शुल्क ₹ 250/–
(डाक व्यय प्रति अंक ₹ 35/– तथा वार्षिक
₹ 100/–अतिरिक्त होगा)
विदेशों में प्रति अंक $ 10, वार्षिक $ 40

मुद्रक – दि प्रिंट्स होम, 20/108, यमुना किनारा, बेलनगंज
आगरा–282004

इस पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं के विचारों से केंदीय हिंदी संस्थान का सहमत होना आवश्यक नहीं है। प्रकाशित सामग्री के उपयोग के लिए स्वामी/प्रकाशक की अनुमति आवश्यक है।

स्वामित्व – सचिव, केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल, आगरा

अनुक्रम

क्र. सं.	आलेख का शीर्षक	लेखक का नाम	पृ. सं.
•	आमुख	बीना शर्मा	05–05
•	संपादकीय	हरिशंकर	06–07
1.	कालिदास कृत रघुवंश महाकाव्य में पर्यावरण शिक्षा की प्रासंगिकता	रमेश प्रसाद पाठक	09–20
2.	बुनियादी तालीम और बुनियादी तालीम शिक्षण–अधिगम पद्धति के प्रति शिक्षकों के मतों का विश्लेषणात्मक अध्ययन	अनूप कुमार सिंह	21–28
3.	शिक्षा में लैंगिक विमर्श : दशा एवं दिशा	कृष्ण बिहारी पाठक	29–33
4.	जनजातीय क्षेत्रों में ऑनलाइन शिक्षा : स्वरूप, समस्याएँ और संभावनाएं	नवीन नंदवाना, सविता नंदवाना	34–39
5.	शिक्षा में पारलैंगिक व्यक्ति की भूमिका	जस्मीन पाटनायक	40–46
6.	कोरोना काल की ऑनलाइन शिक्षा	डी. शंकर	47–52
7.	रामदरश मिश्र और रमेशचंद्र शाह की डायरियों में नैतिक शिक्षा	राधा दुबे	53–59
8.	भारतीय भाषा शिक्षण और हिंदी की उपयोगिता	आशा रानी	60–66
9.	गांधी की सभ्यता की दृष्टि : सभ्यता और संस्कार, शिक्षा का वर्तमान संदर्भ	विनोद कुमार	67–76
10.	भारतीय शिक्षण संकल्पना : आदर्श संकल्पना	अर्चना दुबे	77–81
11.	वेदों में पंचमुखी शिक्षा	मंजू सिंह	82–87
12.	प्राथमिक शिक्षण में मातृभाषा की प्रासंगिकता	रमेश तिवारी	88–92

13.	ऑनलाइन शिक्षण–अधिगम तकनीकी	**इसपाक अली**	93–97
14.	कोरोना महामारी और ऑनलाइन शिक्षण	**सुविद्य धारवाड़कर**	98–104
15.	कक्षायी शिक्षण में बच्चे के सामाजिक अनुभवों की भूमिका : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन	**अभिलाषा बजाज**	105–111
16.	अध्यापक शिक्षा का भारतीयकरण	**अमित कुमार पाण्डेय**	112–117
17.	शिक्षा, समाज और मानव मूल्य	**अरुण कुमार चतुर्वेदी**	118–120
18.	शिक्षा और राष्ट्रीय पुनरुत्थान	**चंद्रकांत तिवारी**	121–131
19.	21वीं सदी में प्रासंगिक होता दर्शनशास्त्र	**संदीप अवस्थी**	132–141
	लेखकों के नाम व पते/इस अंक के लेखक		142–143
	सदस्यता फार्म		144

आमुख

शैक्षिक उन्मेष शिक्षा जगत के विभिन्न पहलुओं के वैचारिक विमर्श की पत्रिका है। शिक्षा के सैद्धांतिक पहलुओं से प्रारंभ होकर इसके व्यावहारिक धरातल तक जाने की प्रक्रिया को उजागर करती है। पर्यावरण शिक्षा, बुनियादी तालीम, लैंगिक विमर्श, ऑनलाइन शिक्षा, हिंदी भाषा शिक्षण, नैतिक शिक्षा, सभ्यता और संस्कृति, शिक्षा की आदर्श कल्पना, वैदिक कालीन शिक्षा, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च स्तरीय शिक्षा, शिक्षा में सामाजिक अनुभवों की भूमिका अध्यापक शिक्षा के भारतीयकरण के संदर्भ हों या राष्ट्रीय पुनरूत्थान और इक्कीसवीं सदी में दर्शन शास्त्र की प्रासंगिकता का संदर्भ हो, शैक्षिक उन्मेष का प्रस्तुत अंक इन सभी धरातलों क संस्पर्श करता है।

शिक्षा के भारतीयकरण की बात बहुत लंबे समय से की जाती रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नी के दस्तावेज ने इस संदर्भ में दस्तक दी है। शैक्षिक उन्मेष के आगामी अंक इस पर आधारित ह ऐसी संकल्पना बन चुकी है। ऐसी शिक्षा जो मनुष्य को मनुष्य बना सके, जागतिक व्यवहार में द कर सके और वास्तव अर्थों में शिक्षित कर सके, ऐसा स्वप्न सारे देशवासी देख रहे हैं। यह स्व अब जल्दी ही पूरा होगा, इस आशा के साथ अंक प्रकाशन में संलग्न संपादक मंडल, परा मंडल और सभी संबंधितों को अनेकशः साधुवाद।

पाठकों से अपील है कि वे पाठकीय प्रतिक्रियाओं से आगामी अंक को समृद्ध करेंगे

शुभास्ते पंथा

(प्रो. बीना
नि

जनजातीय क्षेत्रों में ऑनलाइन शिक्षा : स्वरूप, समस्याएँ और संभावनाएँ

–नवीन नंदवाना, सविता नंदवाना

विगत कई माह से संपूर्ण विश्व कोरोना नामक वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। महामारी भी ऐसी कि जिसने सारे विश्व को एक ही साथ रोक लिया। सभी तरफ हाहाकार है। सामाजिक दूरियों ने व्यक्ति को ऐसा ही बना दिया है कि हर क्षेत्र इस महामारी के प्रकोप से प्रभावित हुआ है। बच्चे, बूढ़े, युवा सभी इससे मुक्ति चाहते हुए पुराना जीवन वापस जीना चाहते हैं। बूढ़े अपनी हम उम्र के साथियों के साथ समय बिताना चाहते हैं तो युवा अपनी पूरी शक्ति के साथ पुन: कार्य में जुटना चाहता है। बच्चों की बात की जाए तो वे पहले की तरह वापस अपने-अपने विद्यालय जाकर अपने सार्थियों संग पढ़ना-लिखना, खेलना-कूदना और अपने हसीन सपनों को पंख देकर एक लंबी उड़ान भरना चाहते हैं। कोविड 19 नामक महामारी के कारण शिक्षा जगत पूर्ण रूप से चरमरा गया है। चारों तरफ ऑनलाइन शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। निजी और सरकारी विद्यालयों में ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जा रही है। विद्यालय अपने संसाधनों और भौतिक स्थितियों के अनुसार इस कार्य को जारी रखने के लिए प्रयासरत है। किंतु देश की विविधता और भौगोलिक परिस्थितियों से हम भली-भाँति परिचित हैं। एक जैसी योजना देशभर में एकरूप में संचालित करना संभव भी नहीं है। शहरों की स्थितियाँ, उनके परिवार की आय, संसाधनों की उपलब्धता, अभिभावकों का शिक्षित न होना आदि कई ऐसे कारण हैं जो कि शहरी और ग्रामीण जीवन की शिक्षा और व्यवस्था को अलग करते हैं।

ऑनलाइन शिक्षा के लिए निजी माध्यमों के स्कूल कई प्रकार के ऑनलाइन शिक्षा सॉफ्टवेयर और अन्य उपादानों के सहारे अपने कार्य को बेहतर तरीके से संपादित करने के लिए प्रयासरत हैं। वहीं इस दौर में विभिन्न सरकारी विद्यालय भी अपने प्रयासों से इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है। पर दोनों की तुलना एक मापदंड पर करना न तो उचित है और न ही व्यवहारोपयोगी। ऑनलाइन शिक्षा के लिए स्कूल विभिन्न प्रणालियों का सहारा ले रहे हैं। कहीं लाइव तो कहीं वीडियो तो कहीं ऑडियो के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जा रही है। इसका एक दुष्प्रभाव यह भी है कि सभी छात्र पूर्ण रूप से मोबाइल के गुलाम होते जा रहे हैं। परंतु विचार करें तो पता चलता है कि आज भी समाज का एक हिस्सा ऑनलाइन शिक्षा से ही कटा हुआ है। ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में जहाँ गरीबी पसरी है, उन बालकों के लिए तो ऑनलाइन शिक्षा किसी और ग्रह से आया हुआ शब्द प्रतीत होता है, जिसे सुनकर वे बड़ी आँखें तरेर कर आश्चर्य करते नजर आते हैं। जिन लोगों के पास दो जून की रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल है, वहाँ

एंड्राइड मोबाइल का सोचना मात्र एक कल्पना सा लगता है। ''जनजाति क्षेत्रों में शिक्षा का सुविधागत ढाँचा कमजोर है और इसी कारण शिक्षा के समान अवसर की अवधारणा पर प्रभाव पड़ा है। राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने इस बात पर बार-बार जोर दिया है कि इस देश के बच्चों को बिना वर्ग जाति तथा आयु भेद के समान प्रकार की शिक्षा मिलनी चाहिए, शिक्षा की समानता के विपरीत, शिक्षा के संबंध में एक प्रकार की गैर-बराबरी पैदा हुई। एक ओर नगरीय क्षेत्रों के भव्य भवनों वाले सुविधा सम्पन्न विद्यालय हैं तो दूसरी ओर साधनविहीन जनजातीय क्षेत्रों के विद्यालय हैं, जिनमें न्यूनतम सुविधाएँ भी उपलब्ध नहीं है।''[1]

जनजाति के अर्थ पर विचार करते हुए ''मजूमदार के लिखते हैं कि कोई जनजाति परिवारों का ऐसा समूह है जिसका एक समान नाम है जिसके सदस्य एक निश्चित भूभाग पर निवास करते है तथा विवाह व्यवसाय के संबंध में कुछ निषेधाज्ञाओं का पालन करते है एवं जिन्होंने एक आदान-प्रदान संबंध तथा पारस्परिक कर्तव्य विषयक एक निश्चित व्यवस्था का विकास कर लिया हो।''[2]

किसी के पास मोबाइल है भी तो सुदूर क्षेत्रों में और विशेष रूप से पहाड़ी आदि क्षेत्रों में जहाँ आदिवासी लोग निवासरत होते हैं वहाँ नेटवर्क की कल्पना करना भी मुश्किल लगता है। इम्पीरियल गजेटियर के अनुसार— ''एक जनजाति समान नाम धारण करने वाले परिवारों का संकलन है, जो समान बोली बोलती है, एक क्षेत्र से संबंधित होते है एवं सामान्यत: ये समूह अंतर्विवाही होते है।''[3] इस कठिन समय में हमारी सरकारों द्वारा भी बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। संपूर्ण तंत्र बच्चों की शिक्षा को लेकर चिंतित है। नितप्रति शिक्षा जगत में नवीन प्रयोग दिखाई पड़ रहे हैं। अगर राजस्थान राज्य की बात की जाए तो यहा कई ऐसे कार्यक्रम ऑनलाइन शिक्षा पहुँचाने के लिए शुरू किए गए हैं। जैसे—स्माइल (सोशल मीडिया इंटरफेस फोर लर्निंग इंगेजमेंट), शिक्षा वाणी कार्यक्रम, हवा महल कार्यक्रम, शिक्षा दर्शन, व्हाट्स एप्प ग्रुप आधारित शिक्षण क्विज प्रतियोगिता, स्माइल-2 कार्यक्रम आदि।

स्माइल (सोशल मीडिया इंटरफेस फोर लर्निंग इंगेजमेंट) एक अभिनव नवाचारी कार्यक्रम है। इसके माध्यम से व्हाट्सएप्प पर सभी विषयों से संबंधित वीडियो प्रसारित किए जाते हैं। प्रात: नौ बजे समस्त पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (पी.ई.ई.ओ.) के माध्यम से अपने अधीनस्थ सभी विद्यालयों के व्हाट्सएप्प ग्रुप पर इसे प्रसारित किया जाता है। इसके बाद सभी अध्यापक अपनी-अपनी कक्षा के अभिभावक ग्रुप पर इसे भेजकर बालकों तक शिक्षा पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं।

इसी तरह एक कार्यक्रम है शिक्षा वाणी कार्यक्रम। इसके तहत राजस्थान में शिक्षा वाणी प्रोग्राम 11 मई, 2020 को आकाशवाणी पर शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत आर.एस.सी.ई.आर.टी. के द्वारा डाइट एवं एम.ओ.यू. के तहत विभिन्न संस्थाओं एवं प्रशिक्षण शिक्षकों द्वारा तैयार कार्यक्रम प्रतिदिन 55 मिनट तक आकाशवाणी प्रसारित किया जाता है। इस

कार्यक्रम के तहत प्राथमिक वर्ग के बच्चों के लिए कार्टून फिल्म-'मीना की कहानियाँ' का प्रसारण पंद्रह मिनट के लिए किया जाता है और एन.सी.ई.आर.टी. के पाठ्यक्रमानुसार कक्षा तीन से आठ एवं कक्षा नौ से बारह तक प्रतिदिन एक पाठ का प्रसारण किया जाता है। हर सप्ताह की रूपरेखा के अनुसार प्रात: 11 : 00 से 11 : 55 तक प्रसार भारती के 25 प्रादेशिक केंद्रों एवं प्रसार भारती एप्प पर शिक्षण सामग्री प्रसारित की जाती है।

इसी प्रकार के अन्य कार्यक्रमों में शिक्षा-दर्शन नामक कार्यक्रम भी है। यह कार्यक्रम 1 जून से 6 जून तक राजस्थान की राज्य सरकार द्वारा चलाया गया। यह कक्षा एक से बारह तक दो स्लॉट में प्रसारित किया गया था। कक्षा एक से आठ तक अपराह्न 12 : 30 से 2 : 30 बजे तक ओर कक्षा 9 : 00 से 12 : 00 तक अपराह्न 3 : 00 से 4 : 15 तक आर.एस.सी.ई.आर.टी. उदयपुर द्वारा प्रसारित किया गया।

बच्चों को तनाव से मुक्त करने एवं मनोरंजन से जुड़ने के लिए शनिवार 'हवा महल' नामक कार्यक्रम की शुरुआत की गई। विविध भारती रेडियो पर शुरू किए गए इस कार्यक्रम की टैगलाइन-'कोरोना समय में बच्चों का झरोखा' है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में उच्च चिंतन कौशल विकसित करने, पठन-पाठन से जोड़ने एवं मनोरंजन है। स्माइल (सोशल मीडिया इंटरफेस फोर लर्निंग इंगेजमेंट) प्रोजेक्ट के मंच द्वारा यह सामग्री शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को प्रेषित की जाती है। पीरामल फाउंडेशन फॉर एजुकेशन और टाटा ट्रस्ट सेंटर द्वारा तैयार सामग्री का प्रसारण आर.एस.सी.ई.आर.टी. उदयपुर द्वारा 2 मई, 2020 से लगातार प्रत्येक शनिवार को किया जा रहा है।

हाल ही में एक व्हाट्स एप्प आधारित एक क्विज प्रतियोगिता का आरंभ किया गया। इसके तहत संपूर्ण राज्य के जिलों को तीन भागों में बाँटकर प्रत्येक भाग के लिए अलग-अलग प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। जिसमें सरकार का उद्देश्य बच्चों को उत्साहपूर्वक शिक्षा से जोड़े रखना है। सभी राज्य सरकारें इस तरह के कई प्रयास अपने-अपने स्तर पर कर रही हैं। केंद्र सरकार भी समय-समय पर अपनी गाइडलांइस के माध्यम से राज्य सरकारों को उचित दिशा-निर्देश दे रही है।

''स्माइल-2 कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिखित कार्य की जांच, संकलन एवं आकलन के लिए प्रारंभ किया गया है। इस प्रोग्राम के तहत विद्यार्थियों तक न सिर्फ गृहकार्य पहुँचाएगा जाएगा बल्कि उनके द्वारा किए गए गृहकार्य की नियमित जांच भी होगी एवं जांच के पश्चात इसे विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो में संधारित किया जाएगा जो कि बाद में उनके सत्रीय समेकित आकलन का आधार बनाया जा सकेगा। सप्ताह में एक बार कक्षा 1-5 के लिए तथा सप्ताह में 2 बार कक्षा 6-8 के लिए गृहकार्य व्हाट्स एप्प (whatsapp) के माध्यम से भेजा जाएगा जिसे कक्षाध्यापक (मूलत: संस्था प्रधान) प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुँचाना सुनिश्चित करेंगे। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि अभिभावक के पास प्रिंट की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो विद्यालय द्वारा गृहकार्य प्रिंट करवाया जाएगा तथा 2 बजे बाद संबंधित अध्यापकों द्वारा कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए विद्यार्थियों हेतु गृहकार्य वितरण/संकलन का कार्य किया जाएगा।''[4]

जहाँ तक शहरी क्षेत्रों के बच्चों का सवाल है, वो तो किसी न किसी प्रकार से इस ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम से जुड़े हैं लेकिन ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में यह उतना संभव नहीं है। जहाँ लोग भोजन, वस्त्र, आवास, बीमारी आदि प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संघर्षरत हैं, ऐसे में ऑनलाइन शिक्षा के लिए आवश्यक संसाधन मोबाइल, लेपटॉप आदि जुटा पाना दुष्कर लगता है। विविध सरकारी योजनाएँ उनके इस संकटकाल में सहायक तो हो रही है पर नए संसाधनों की उपलब्धता कई परिवारों के लिए भी एक स्वप्न सा लगता है। उच्च शिक्षा से जुड़े कई विद्यार्थी भी इस ऑनलाइन के दौर में कई कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं तो ऐसे में स्कूली शिक्षा के छोटे बच्चों के लिए ये समस्त बातें सोचना कठिन लगता है।

सरकार एवं शिक्षा जगत से जुड़ा वर्ग पूर्ण रूप से प्रयासरत है कि प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित हो परंतु फिर भी ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के गरीब परिवारों के विद्यार्थी इस ऑनलाइन शिक्षा से वंचित है।

मूल समस्या सिर्फ संसाधनों की अनुपलब्धता, गरीबी या नेटवर्क की उपलब्धता आदि की समस्या ही नहीं है वरन अभिभावकों का जागरूक न होना भी ऑनलाइन शिक्षा में एक बड़ी बाधा बना हुआ है। आदिवासी क्षेत्रों की बात की जाए तो जहाँ एक-एक घर के बीच एक-एक किलोमीटर की दूरी है और वे पूरी तरह से पहाड़ी क्षेत्रों में निवासरत हैं। इन अभिभावकों के पास शिक्षा की कमी तो है ही स्वयं अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर जागरूकता का भी उनमें अभाव दिखाई पड़ता है। ये कारण ऐसे हैं जो शिक्षा की खाई को और अधिक चौड़ा करते हैं।''जहाँ 4जी नेटवर्क की संभावना भी नहीं। उन दूर दराज के इलाकों में इस ऑनलाइन को कैसे देखेंगे, जहाँ अभी बिजली और सड़क भी नहीं पहुँचे। जिन घरों में यह सब है भी उनमें भी क्लासरूम की सामूहिकता और एकाग्रता का माहौल बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। ऐसे में ऑनलाइन शिक्षा वर्तमान संकट की घड़ी में 'मजबूरी में जरूरी' तो हो सकता है, पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विकल्प बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कुछ लोग ऑनलाइन शिक्षा में सामाजिक भेदभाव को देख रहे हैं। उनका तर्क है कि पिछड़े तबके पास स्मार्टफोन, कंप्यूटर, डेटा, आदि नहीं है, इसलिए वे ऑनलाइन के लाभ से वंचित रह जाएंगे। यह चिंता सही है। यह कोरोना संकट की तात्कालिक समस्या से उपजी परिस्थिति है। स्मार्टफोन, कंप्यूटर, डेटा आदि की लागत और क्लास रूम शिक्षा की लागत का अंतर अगर देखें तो समझा आ जाएगा कि इसी तर्क का इस्तेमाल कर दलित-पिछड़े तबके को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से बाहर किया जा रहा है। उन्हें ऑनलाइन की तरफ धकेला जा रहा है। सरकार गरीब दलित पिछड़ों को इन तकनीकी सुविधाओं के जरिये ऑनलाइन शिक्षा का विकल्प देने की बात कर रही है। उसे ही वे सस्ती शिक्षा और गुणवत तापूर्ण शिक्षा का नाम दे रहे हैं। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज (MOOCs) पर जोर इसी कारण से दिया जा रहा है।''[5]

माता-पिता एक ओर अपने बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा को लेकर लापरवाह हैं। वे बच्चों के स्कूल न जाने को अवकाश समझकर अपने बच्चों को विविध घरेलू और कृषि आदि के कार्यों में व्यस्त कर रहे हैं। घर पर एक ही मोबाइल यंत्र उपलब्ध होना भी एक ही परिवार के एकाधिक बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा में बाधक है। कई घरों में आज भी स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं है। इस कारण भी बच्चे ऑनलाइन शिक्षा से न जुड़ पाने के कारण पिछड़ रहे हैं। घर पर एक ही मोबाइल फोन होता है और उसे भी कोई बड़ा अपने पास ही रखता है। लगभग सभी परिवारों के लोग या तो मजदूरी करते हैं, या खेती उनका जीवनाधार है। शिक्षक यदि यह चाहे कि अपने विद्यार्थी से संपर्क कर उसे अध्ययन आदि के लिए प्रोत्साहित करे तो वह भी इस कारण संभव नहीं हो पाता है। अभिभावकों का शैक्षिक स्तर भी बच्चों के शिक्षण को प्रभावित करता है। एक तरफ कोविड की मार तो दूसरी तरफ बेरोजगारी और तीसरा बच्चों की शिक्षा। इन सभी में तालमेल बिठा पाना इन आदिवासी क्षेत्र के लोगों के लिए असंभव-सा लगता है। लंबे समय से बंद पड़े विद्यालयों से छात्रों की पढ़ाई का बहुत असर हुआ है। इस बंद के दौरान ग्रामीण और आदिवासी लाग अपने बच्चों को शहरी माता-पिता की तरह शिक्षा का एक उचित वातावरण प्रदान करने में असमर्थ रहे हैं। क्षेत्रों में कहीं भी पुस्तकालय या वाचनालय का ना होना भी शिक्षा की राह में रोड़ा है।

इस कठिन दौर में यह लोग बहुत प्रभावित हुए हैं। इसी के साथ इनकी अशिक्षा, गरीबी और जीवन की कठिनता ने छात्रों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी बहुत ही प्रभावित किया है। कई बालकों को तो बाल श्रम में लगना पड़ा तो कई घरेलू कामों में लगकर अपने माता-पिता का सहयोग कर रहे हैं। इन सभी कारणों से उनकी शिक्षा, अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया पर विराम लग जाता है। माना कि ऑनलाइन शिक्षण आज के समय की माँग है, अगर यह कदम भी नहीं उठाते तो शायद ग्रामीण और शहरी दोनों बालकों की स्थिति एक जैसी होती। प्रसिद्ध आदिवासी कवयित्री निर्मला पुतुल की कविता की ये पंक्तियाँ हमें आदिवासी जीवन के यथार्थ से अवगत कराती है-

''पीढे पर बैठ/टिबरी की टिमटिमाती रोशनी में।
पत्तल टिपती माँ/कब सोती जागती/हम नहीं जानते।
कितना जागती है/हमारी नींद के लिए।
क्या माँ सचमुच धरती है/जो कभी नहीं थकती है।
कुल्ही में बैलगाड़ी के/चरमराहट से बजती है।
सुबह की घंटी/माथे के ऊपर/टघरते सूरज से बजते हैं बारह।
गाय बकरी के घर लौट आने से भाम।
आकाश में सप्तऋषि तारों को चमकते देख/होती है उनके लिए रात।''[6]

इस दौर में जो स्थितियाँ हमारे समक्ष उभरकर आई हैं इससे हमें यह सीख लेनी होगी कि हमें कक्षा-कक्ष शिक्षण के साथ ऑनलाइन शिक्षा के विकल्प पर भी तैयार रहना होगा। हमारी

सरकारों को इस विषय में सोचकर उचित कार्य योजना बनानी होगी। जिससे कि कठिन स्थितियों में भी हम काम कर सकें। जनजातीय क्षेत्रों में इसके लिए विशेष बजट रखना होगा जिससे कि उन क्षेत्रों के नेटवर्क और अन्य समस्याओं पर निजात पाया जा सके। साथ ही अब सरकारों को वार्षिक और पंचवार्षिक योजनाओं में इसके लिए विशेष प्रावधान करने चाहिए। क्षेत्र के भामाशाहों को तैयार कर जरूरत मंद विद्यार्थियों की मदद करवाने का प्रयास भी रहना चाहिए। यदि शिक्षक वर्ग की वास्तविकता की पड़ताल की जाए तो पता चलता है कि शिक्षकों का एक बड़ा वर्ग भी अभी तक तकनीकी से पूरी तरह परिचित नहीं है। वे भी परंपरागत प्रणाली को ही अपनाए हुए हैं। अत: ऐसे में शिक्षकों को भी तकनीकी के प्रशिक्षण दिए जाने आवश्यक है। क्षेत्र के विधायकों और सांसदों के मद से जनजातीय ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों को तकनीकी संपन्न करने के लिए अनुदान जारी किया जाना चाहिए।

ऑनलाइन शिक्षा की महत्ता इस संकट काल में बढ़ी है किंतु हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि कक्षा शिक्षण का विकल्प कभी भी ये ऑनलाइन कक्षाएँ नहीं हो सकती हैं। फिर भी आपातकाल में ये एक वरदान बनकर सिद्ध हुई हैं। हमें अब इन ऑनलाइन शिक्षा के ग्रामीण और शहरी के भेद को तो मिटाना ही है, साथ ही जनजातीय ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं का हल करके उनको भी उचित सुविधाएँ उपलब्ध करानी होंगी।

संदर्भ–

1. डॉ. आशुतोष व्यास : जनजातीय समाज और प्राथमिक शिक्षा, अंकुर प्रकाशन, उदयपुर, 2009, पृ. 149
2. https://www.kailasheducation.com/2019/19/janjati-arth-paribhasha-visheshta.html
3. https://www.kailasheducation.com/2019/19/janjati-arth-paribhasha-visheshta.html
4. https://www.cce.guru/2020/11/SMILE-2-Guideline-and-Homework.html#gsc.tab=0
5. https://thewirehindi.com/122150/covid-19-lockdown-online-classes-higher-education
6. निर्मला पुतुल : बेघर सपने, नगाड़े की तरह बजते शब्द, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, 2005, पृ. 11-12